*क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिमान परिवर्तन हो रहे हैं?**

शक्तिकांत दास

भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) राष्ट्रीय परिषद, के सदस्यों के साथ इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे यह देख कर खुशी हो रही है कि उदय कोटक, श्री टीवी नरेंद्रन, श्री संजीव बजाज, श्री चंद्रजीत बनर्जी और अन्य प्रमुख सदस्यों के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में 2020-21 में सीआईआई ने अपने कार्य और विचार प्रक्रियाओं को एक नए विषय के केंद्र में रखा है - नए विश्व के लिए भारत का निर्माण: जीवन, जीविका, संवृद्धि।

वर्तमान में कोविड-19 हर चर्चा का एक अपरिहार्य विषय हो गया है। हर तरफ़इस कर्व को फ्लैट करने; एक मारीचिकेय टीके के आगमन; जीवन व जीविका को बचाने और होने वाले आर्थिक समुत्थान के आकार को लेकर प्रश्नों की बाढ़ सी है। ये प्रश्न दिन-रात हमारा पीछा कर रहे हैं और अभी तक कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं है। अभी के लिए बस एक बात पक्की है कि हमें अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़नी है और जीत कर निकलना है।

आज मैंने सोचा कि इस अनिश्चित वर्तमान से कुछ अलग हटकर भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिमान परिवर्तनों पर कुछ चिंतन किया जाए। हो सकता है कि महामारी के सर्वग्रासी चिंतन के कारण इन पर हमारा ध्यान न गया हो। परंतु हो सकता है इनमें संभावना पल रही हो सुधार की, पुनर्निर्माण की और विकास की आकांक्षाओं के साथ हमारी मुलाकात को कोई एक नया रूप देने की। ये परिवर्तन कुछ समय से घटित हो रहे हैं और अभी अपने प्रारंभिक दौर में हैं। इनको समझने और इन परिवर्तनों का हमारे भविष्य को आकार देने में जो हाथ हो सकता है उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको जरा पीछे हटकर एक अधिक मध्यावधि दृष्टि लेनी होगी। अपने संबोधन में मैं ऐसे पाँच प्रमुख गतिमान परिवर्तनों की चर्चा करना चाहूँगा: (i) भाग्य चक्र का कृषि क्षेत्र की तरफ मुड़ना; (ii) ऊर्जा क्षेत्र के घटकों का नवीकरणीय विकल्पों के पक्ष में जाना (iii) संवृद्धि को गति देने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी) तथा स्टार्ट-अप्स का उपयोग (iv) घरेलू और वैश्विक दोनों की आपूर्ति व मूल्य श्रृंखलाओं में परिवर्तन और (v) और संवृद्धि की गति बढ़ाने वाली बुनियादी संरचना।

I. भाग्य चक्र का कृषि क्षेत्र की तरफ मुड़ना

यह बिलकुल सपष्ट है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन आया है। पिछले दशक में 3.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में खाद्यान्न का उत्पादन 296 मिलियन टन पर पहुंच गया। बागबानी उत्पादन भी पिछले 10 वर्षों में 4.4% की वार्षिक औसत दर से बढ़ते हुए 320 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर आ गया। भारत विश्व में अब दूध, अनाजों, दालों, सब्जियों, फलों, मछली, मुर्गी एवं मवेशी के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। अन्न का वर्तमान बफर स्टॉक 91.6 मिलियन टन का है जो बफर के मानक से 2.2 गुना अधिक है। ये उपलब्धियां मेरी दृष्टि में वर्तमान परिदृश्य में आशा की सबसे प्रखर किरणे हैं।

व्यापार की शर्तों का कृषि के पक्ष में जाना वह कुंजी है जो इस गतिशील परिवर्तन को कायम रखेगी और कृषि में सकारात्मक आपूर्ति प्रतिसाद पैदा करेगा। अनुभव दिखलाता है कि व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल रहीं तो कृषि जीवीए की वार्षिक औसत वृद्धि 3% से अधिक रही है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्य साधन रहा है किंतु सबक यह रहा है कि कीमत संबंधी प्रोत्साहन महंगे, अपर्याप्त और स्वरूप बिगाड़ने वाले भी रहे हैं। भारत अब एक ऐसे चरण में पहुँच गया है जहां अधिशेष प्रबंधन (सरप्लस मैनेजमेंट) एक बड़ी चुनौती बन गया है। नीति के स्तर पर हमें ऐसी रणनीतियां अपनानी होंगी जिसमें उपभोक्ताओं के लिए वाजिब कीमतें हों और किसानों की आय भी बढ़े।

एक कुशल घरेलू आपूर्ति श्रृंखला यहाँ महत्त्वपूर्ण हो जाती है। तदनुसार, अब उन प्रमुख सुधारों का लाभ उठाने पर ध्यान देना होगा जो कृषि में नि:शुल्क व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन से वेयर हाउस, प्रशीतन गृह (कोल्ड

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक - 27 जुलाई, 2020 को भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) राष्ट्रीय परिषद, मुंबई को संबोधन।

स्टोरेज), तथा बाज़ार-स्थलों के साथ-साथ आपूर्ति-श्रृंखला अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन की प्रत्याशा है । दूसरा, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुगमन) अध्यादेश [फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) ऑर्डिनेंस] 2020 का लक्ष्य कृषि उत्पाद में बाधा-रहित व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। तीसरा, फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एस्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज़ ऑर्डिनेंस, 2020, कृषकों को प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोकविक्रेता, बड़े फुटकर विक्रेता तथा निर्यातकों से प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से लेन-देन का अधिकार देगा। इस सशक्तिकारी कानूनी ढांचे के साथ ध्यान इन बातों पर केंद्रित किया जाना चाहिए: (ए) फसलों का विविधीकरण, जलभक्षी (अधिक पानी पीने वाली) फ़सलों (वाटर गजलर्स) पर जोर कम, (बी) खाद्यान्न प्रसंस्करण जो कृषि उत्पाद की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ़) को बढ़ाए तथा फसल कटने के बाद बरबादी में कमी लाए; (सी) कृषिगत निर्यात जो भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम बनाए तथा (डी) कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी पूंजी निर्माण। कृषक आय को दुगुना करने से संबंधित समिति की प्रत्याशा है कि कृषि में निजी निवेश 2015-16 के ₹61000 करोड रुपए से बढ़कर 2022-23 तक ₹139,424 करोड़ हो जाएगा। इन सभी प्रयासों ने उद्योग और व्यवसाय के लिए अवसरों की एक नई दुनिया खोल दी है। रोजगार सृजन और किसानों की आय में इसके परिणाम स्वरूप होने वाली वृद्धि बहुत बड़ी हो सकती है।

II. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ता ऊर्जा उत्पादन का स्वरूप

अवसर का ऐसा ही आकाश अब ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद है, विशेषत: नवीकरणीय ऊर्जा में । बिजली के क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने में भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही है। यह ऊर्जा अधिशेष वाला देश बन गया है जो पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात करता है। 2015-16 से 2019-20 के बीच भारत में बिजली की मांग औसतन 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि आपूर्ति 4.5% के औसत दर से तथा इसी अवधि में स्थापित क्षमता 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका विशेष उल्लेखनीय है । समग्र स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश मार्च 2015 के अंत के 11.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में दुगुना होकर 23.4 प्रतिशत हो गया। विगत 5 वर्षों में कुल स्थापित क्षमता में कुल वृद्धि का 66.6% नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में रहा है जिसने विद्युत के वृद्धिशील उत्पादन में 33.6 प्रतिशत का योगदान दिया है। इस उछाल का लगभग 90 प्रतिशत सौर और पवन ऊर्जा से आया है । इस शानदार प्रगति ने भारत के लिए 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 40% करने के लक्ष्य की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है । हरित ऊर्जा की ओर जाने से कोयला आयात बिल घटेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नए निवेश का सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन लागत में बड़ी कमी ऊर्जा मिश्रण में बदलाव को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारक रहा है । फलत: दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में नवीन क्षमता सृजन में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की तकनीकें न्यूनतम लागत वाला विकल्प बन गई हैं । नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि की भारित औसत लागत 2019 में भारत में दुनिया में सबसे कम रही । इसने बिजली की हाजिर (स्पॉट) कीमतों पर उल्लेखनीय अधोमुखी दबाव डालना शुरू कर दिया है।

आगे चलकर यह उल्लेखनीय प्रगति, ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण बदलाव में परिणत हो सकती है जिसमें विनियमन, विकेंद्रीकरण और सक्षम मूल्य संधान शामिल होंगे । वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ), बढ़े हुए मूल्यह्रास लाभ व्यवहारिकता अंतराल निधियन (वायाबिलिटी गैप फंडिग) और ब्याज दर अनुदान जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में नीतिगत हस्तक्षेपों को पुनर्विचार/ समीक्षा से गुजरना होगा । वाणिज्य, तकनीकी और संचरण क्षतियों में कमी लाते हुए बिजली के खुदरा वितरण में सुधार एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। अन्य क्षेत्रों के लिए क्रॉस-सब्सिडी का उन्मूलन और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) में अंतराल मिटाने के लिए त्वरित

डिस्कॉम सुधारों (निजीकरण और स्पर्धा सहित) की आवश्यकता होगी । जब और जहाँ नवीकरणीय स्रोत उत्पन्न हो वहाँ से सप्लाइ ले सकने वाले एक राष्ट्रव्यापी ग्रीड एकीकरण की जरूरत है ताकि नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित दैनिक व मौसमी उतार-चढ़ाव को संभाला जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों में ये गतिमान परिवर्तन भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत को बढ़ाने में सहायक हो सकता हैं जो विश्व में न्यूनतम में से एक है । यहाँ भी भारतीय उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

III. संवृद्धि को गति देने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा स्टार्ट-अप्स का उपयोग

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पिछले दो दशकों से अधिक समय से भारत की आर्थिक प्रगति का एक इंजन रहा है। गत वर्ष आईसीटी उद्योग ने भारत की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान दिया तथा शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार निर्माता रहा । 2019-20 में अमेरिका को यूएस $ 93 बिलियन के सॉफ्टवेयर निर्यात ने भारत के कुल सेवा निर्यात में से 44% का योगदान दिया और विगत 5 वर्षों में भारत के पण्य व्यापार घाटे का 51% फाइनेंस किया।

हालाँकि, नजर में आने वाले ये प्रमुख आँकड़े (हेडलाइन नंबर्स) अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को ठीक से नहीं बता पाते। आईटी ने सभी क्षेत्रों में कार्य प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी है और चारों ओर उत्पादकता लाभ उत्पन्न किए हैं । आईसीटी क्रांति ने भारत को ज्ञान आधारित समाधानों के एक सक्षम, विश्वसनीय और कम लागत वाले आपूर्तिकर्ता के रूप में वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया है । भारतीय आईटी फर्में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), रोबोटिक्स तथा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशंस का विकास करने में सबसे आगे हैं। इसने एक नवोन्मेष /नवप्रवर्तन केंद्र (इनोवेशन हब) के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद की है, जिसमें कई स्टार्ट-अप्स ने यूनीकॉर्न स्टेटस (यूएस $ 1 बिलियन का वैल्यूएशन) प्राप्त किया है । भारत ने 2019 में 7 नए यूनीकॉर्न देकर, कुल गिनती 24 तक पहुँचा दी, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है[1]।

'स्टार्ट-अप इंडिया' अभियान देश के युवा उद्यमियों की क्षमताओं को पहचान प्रदान करता है तथा इसका लक्ष्य उन्हें एक सहायक परितंत्र (ईकोसिस्टम) उपलब्ध कराना है । ट्रैक्ससीएन डेटाबेस के अनुसार, भारतीय टेक स्टार्ट-अप को मिलने वाली फंडिंग 2019 में यूएस $ 16.3 बिलियन को छू गई, जो एक साल पहले के स्तर से 40 प्रतिशत से अधिक है । हेल्थटेक और फिनटेक जहाँ अग्रणी क्षेत्र हैं, सभी सेक्टरों और बाजारों में उद्यमी अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, और इस परितंत्र की गहराई और व्यापकता को बढ़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में स्टार्ट-अप का एक बड़ा हिस्सा छोटे और मंझोले व्यवसायों तथा निम्न व मध्यम आय वर्गों को सेवा दे रहा है।

कोविड-19 ने स्टार्टअप्स के परिदृश्य को प्रभावित किया है, विशेषत: व्यापक रूप से फैली हुए जोखिम विमुखता के माहौल के कारण धन (फंड) की उपलब्धता के मामले में । कोविड-19 से पहले भी, एक वैश्विक तकनीकी मंथन चल रहा था, जिसमें कंपनियां गतानुगतिक (लीगेसी) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम पर खर्च कम कर रही थीं, लेकिन डिजिटल टेक्नलॉजियों और कंप्यूटिंग/विश्लेषणात्मक क्षमताओं में तेजी से प्रगति हो रही थी। दुनिया के अग्रणी आउटसोर्सिंग केंद्र के रूप में भारत की पोजीशन के लिए वैसी अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से भयंकर प्रतिस्पर्धा तेजी से एक चुनौती बनकर उभर रही है जो किफायती आईटी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं । वैश्विक स्तर पर, वर्क परमिट और आप्रवास (इमिग्रेशन) नीतियों से संबंधित नियामक अनिश्चितता भी चुनौतियों को बढ़ा सकती है। इस क्षेत्र को डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दों से भी निपटना है।

सृजनात्मक विध्वंस एक मजबूत गतिशील अर्थव्यवस्था की एक अभिन्न विशेषता है। इस प्रक्रिया आगे बढ़ाने और इसके परिणामों को संभालने में आईटी सेक्टर सबसे अच्छी स्थिति में है। किसी जिले में पनपने वाली नई फर्मों की संख्या और वहाँ के सकल घरेलू उत्पाद के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है[2]। भारत में अधिक रोजगार सृजन और उच्च उत्पादकता वाले आर्थिक विकास के लिए युवा फर्मों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना

[1] नैस्कॉम: इंडियन स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, 2019 (नवंबर)।

[2] आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, अध्याय 2 और 3, भारत सरकार।

महत्वपूर्ण होगा। संसाधन और नीतिगत ध्यान को इस दिशा में मोड़ना आवश्यक होगा। नवोन्मेष तथा विचारों को पोषण देकर मूर्त रूप देने की क्षमता प्रमुख चुनौती होगी। इस संदर्भ में निजी उद्यम और निवेश की भूमिका पासा पलटने वाली होगी।

IV. आपूर्ति / मूल्य श्रृंखला में बदलाव - घरेलू और वैश्विक

एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था में, एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला आर्थिक कल्याण को बढ़ा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत उत्पादनोत्तर एवं उत्पादन-पूर्व सहबद्धताओं (फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) वाले क्षेत्रों में निवेश से अधिक उत्पादन, आय और रोजगार पैदा हो सकता है। फलत:, ऐसे क्षेत्रों की पहचान रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है । मजबूत अंतर-क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं की सक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में किसी देश की स्थिति को मजबूत करने से खुलेपन के लाभों को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। जीवीसी में किसी उत्पाद के प्रारंभिक चरण से लेकर उसकी डिजाइनिंग, उत्पादन, विपणन, वितरण और बिक्री के बाद सपोर्ट सर्विसेज़ से शुरू होने वाली गतिविधियों की पूरी श्रृंखला समाहित है जिसमें विभिन्न देशों में स्थित कई फर्म और श्रमिक शामिल हो सकते हैं। किसी देश की जीवीसी की भागीदारी जितनी अधिक होगी, व्यापार (ट्रेड) से उतने ही अधिक लाभ होंगे क्योंकि इसमें शामिल देश जीवीसी में दूसरों के तुलनात्मक लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। जीवीसी के माध्यम से दो-तिहाई से अधिक विश्व व्यापार होता है।

विश्व बैंक (2020)[3] के शोध निष्कर्ष बताते हैं कि जीवीसी भागीदारी में एक प्रतिशत की वृद्धि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय स्तर को एक प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकती है। जीवीसी भागीदारी सूचकांक के अनुसार भारत का जीवीसी एकीकरण (कुल सकल निर्यात के अनुपात में 34.0 प्रतिशत), आसियान देशों (कुल सकल निर्यात के अनुपात में 45.9 प्रतिशत) की तुलना में कम है। इसे बदलने की जरूरत है।

कोविड -19 और अन्य घटनाओं के फलस्वरूप जीवीसी में वैश्विक परिवर्तनों से भारत के लिए अवसर पैदा होंगे। आयात के स्रोतों के विविधिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, अधिक रणनीतिक व्यापार एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक हो सकता है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का जल्दी पूरा किया जाना शामिल होगा।

V. संवृद्धि की गति बढ़ाने वाली बुनियादी संरचना

विगत पाँच वर्षों में भारत में भौतिक आधारभूत संरचना में हुई प्रगति को किसी गतिमान परिवर्तन से कमतर नहीं देखा जाना चाहिए। भारत में परिवहन के प्राथमिक माध्यम, सड़क का निर्माण 2015-16 के 17 किमी प्रतिदिन से बढ़कर गत वर्षों में लगभग 29 किमी प्रतिदिन हो गया है। 142 एयरपोर्टों वाला भारत नागर विमानन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के ग्लोबल कम्पीटीटिवनेस रिपोर्ट 2019 में एयरपोर्ट संपर्क (कनेक्टिविटी) में भारत चौथे स्थान पर है। फरवरी 2020 में दूरसंचार में, समग्र टेली-घनत्व (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या) 87.7 प्रतिशत थी। भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पैठ में तेजी से वृद्धि हुई है। कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2014 के 610 लाख से दस गुना बढ़कर फरवरी 2020 में 6811 लाख तक पहुँच गए जिससे इंटरनेट ट्रैफिक में बड़ा विस्तार हुआ है। मासिक डेटा की खपत में भारत दुनिया में अग्रणी है जहाँ प्रति माह प्रति ग्राहक (सब्सक्राइबर) औसत खपत 2014 के 62 एमबी से 168 गुना बढ़कर 2019 के अंत में10.4 जीबी हो गई। डेटा की लागत भी दुनिया में निम्नतम में से एक है जिससे लाखों लोगों को इंटरनेट किफायत पर मिल रहा है।

नौपरिवहन उद्योग (शिपिंग इंड्स्ट्री) बाह्य पण्य वस्तु व्यापार के रीढ़ की हड्डी है क्योंकि लगभग 95 प्रतिशत व्यापारिक मात्रा (ट्रेडिंग वॉल्यूम) समुद्री मार्गों से जहाजों के माध्यम से पहुँचाई जाती है । भारतीय बंदरगाहों की औसत प्रतिवर्तन अवधि (टर्नएराउंड टाइम), जो क्षमता का सूचक मानी जाती है, 2012-13 के 102.0 घंटों से सुधरकर 2018-19 में 59.5 घंटे हो गई। बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में पहले ही कह चुका हूँ। रेलवे में पूर्वी व पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई मार्ग (ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स) का तेजी से

[2] वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (2020), "ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंटइन द एज ऑफ़ वैल्यू चेन्स", वर्ल्ड बैंक।

विकास किया जा रहा है जिससे माल ढुलाई प्रभार (फ्रेट चार्ज) में काफ़ी कमी आने की संभावना है। 2019-20 में कुल 15 महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गईं जिनकी ट्रैक लंबाई लगभग 562 किमी होगी तथा 2019-20 में कुल 5782 रूट किमी का रेलवे विद्युतीकरण भी पूरा किया गया। शहरी सामूहिक परिवहन की मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

इस प्रगति के बावजूद, बुनियादी ढांचे में अभी भी बड़ी कमी बनी हुई है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, देश को 2030 तक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लगभग $ 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण के विकल्पों के मामले में, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में बैंकों के अत्यधिक एक्सपोज़र के नतीजों से हम अभी उबर ही रहे हैं। स्पष्ट रूप से वित्तपोषण विकल्पों में विविधता लाने की आवश्यकता है। 2015 में नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की स्थापना इस दिशा में नीतिगत स्तर पर एक प्रमुख रणनीतिक कदम है। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा, दबावग्रस्त एसेट्स की समस्या के लिए बाजार आधारित समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूतिकरण तथा उचित मूल्य निर्धारण और उपयोगकर्ता प्रभार (यूजर चार्ज) की वसूली आदि विषयों की नीतिगत स्तर पर प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह, कुछ लक्षित विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की दिशा में एक बड़ा प्रयास अर्थव्यवस्था में फिर से प्राण फूँक सकता है। इसकी शुरुआत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेसवे के रूप में उच्च गति रेल मार्ग के साथ हो सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों तथा रेल / सड़क नेटवर्क के आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादनोत्तर व उत्पादनपूर्व सहबद्धताएं (बैकवर्ड एंड फॉर्वर्ड लिंकेज) उत्पन्न करेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश हमारे बुनियादी ढांचे में निवेशों के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) इस संबंध में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

आज के अपने संबोधन में, एक महामारी की दुश्चिंता से बोझिल परिदृश्य से अलग हटकर मैंने आशावाद की ओर जाने की कोशिश की है। अपनी अर्थव्यवस्था के इन गतिमान बदलावों को संरचनात्मक परिवर्तनों में रूपांतरित करना होगा जिसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मिले और राष्ट्रों के समूह में भारत को एक अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक हों। इनमें कठिन परीक्षा की चुनौती है पर बड़े लाभ भी हैं। यह एक मौन क्रांति हो सकती है जिसमें भारतीय उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या सीआईआई इसको नेतृत्व दे सकता है? मैं आपको ये विचार दिए जा रहा हूँ और दे रहा हूँ चुनौती, सपने देखने की।

धन्यवाद।